

राहुल गांधी कानून का सम्मान करें, अराजकता न फैलाएं: रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली, एप्रैल २०११। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राहुल गांधी के संसद मार्ग थाने के बाहर किए गए विरोध प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला। भाजपा के मुताबिक जिस मामले को लेकर राहुल गांधी धरना दे रहे हैं, उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी है। राहुल गांधी बिना पूर्व अनुमति मिले मामले में बाहर घरेने पर बैठे, जबकि पुलिससांसद पहले स्पष्ट कर चुकी है कि मामले में एफआईआर प्रसाद है और जांच जारी है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में गठित समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें दो अन्य न्यायाधीश, सीबीआईआर के पूर्व निदेशक और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गोली चली थी या नहीं, यह भी इसी समिति की जांच का विषय है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, क्या राहुल गांधी को जानकर के शासन का कोई सम्मान नहीं है? क्या वे अपनी मर्जी से कहीं भी जाकर धरना देंगे और अराजकता फैलाएंगे? भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर अराजकता की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह बिना अनुमति या पूर्व सूचना के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर घरेने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने राहुल गांधी को जानकारी दी है कि जिस घटना का वह जिक्र कर रहे हैं, उसमें पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और मामले की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की जांच एक हाई-पावर्ड जज कमेट्री गठित की है।

**जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में
पैलेट गन के इस्तेमाल का
आदेश किसने दिया : कांग्रेस**

नई दिल्ली, एंजेंसी। काग्रिस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। बताया गया कि वे जंतर-मंतर और कर्नाट प्लेस में हुए आंदोलनों के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल से प्रभावित आदिश्रद्ध के मामले में जानकारी लेने आए। एफआईआर दखल कराने की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस स्टेशन के बाहर काग्रिस नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आईवॉल्टेज ड्रामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने प्रकरारों से बचावती भी आरोप लगाया कि 20 जुलाई को कर्नाट प्लेस में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने दावा किया कि साइलेंट के शरीर में 200 से ज्यादा छेद लगे हैं और उसकी आंख में तीन छेद लगे हैं। उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट की रिपोर्ट में भी शरीर में बड़ी संख्या में छेद होने की बात ज्ञात है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार सुबह भी वे एक पुलिस स्टेशन गए थे, जहां से उन्हें दूसरे थाने जाने के लिए कहा गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शिकायत पर कारवाई करने के बजाय पीड़ित पक्ष को लगातार परेशान किया जा रहा है। काग्रिस सांसद मुकुल वासनिक ने भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जांच अपनी जगह जानी रहेगी लेकिन सच्चाई पहले यह पता लगना चाहिए कि कथित तौर पर कौन लगी लाठियों के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। क्या इस कारवाई का आदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था या किसी और ने।

अयोध्या, एजेंसी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने गुरवार को बयान के रूप में नौ पन्नों की चिट्ठी जारी की। उन्होंने मिश्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र को लेकर कई अहम दावे किए। राय ने कहा है कि मिश्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर निर्माण से जुड़े कई झूठे दावे फैलाए हैं। यही नहीं फैलाए लोहे समय उन्होंने किसी अन्य के फैसले को महत्व नहीं दिया।

चंपत राय ने दावा किया कि मंदिर निर्माण के फैसलों में नृपेंद्र मिश्र के फैसले प्रमुख रहे ।

उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनाया, उसमें 15 ट्रस्टी लिखे गए। इसके अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र बनाए गए। राय ने कहा कि उन्हीं

[illegible]

के सुझावों के आधार पर एल एंड टी को मंदिर निर्माण के लिए चुना गया। उन्होंने बताया कि भवनों ने निर्माण के लिए नोएडा की फर्म डिजाइन एक्सोसिएट (फर्म प्रमुख जय काकतीकर) को नृपेन्द्र मिश्रा ने ही चुना।

उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि यह भी सत्य है कि नृपेन्द्र मिश्र के कारण

पत्थरों से बना इतना विशाल मंदिर जून 2020 में कोरोना काल से प्रारम्भ होकर जून 2026 तक पूर्ण रूप से समाज को समर्पित हो गया। यह केवल नृपेन्द्र मिश्र के प्रयत्नों का परिणाम है। जब कभी कोई बाधा आई तत्काल संबंधित विषय के देश के योग्यतम व्यक्तियों को उन्होंने निवेदन

पीएम मोदी ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के प्रमुखों से की मुलाकात

भारत को वैश्विक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने का किया आह्वान

नई दिल्ली, एजेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित सेवा तथैयें में भारत के 20 प्रमुख अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीओओ) और संस्थापकों (फाउंडर्स) के साथ बार्चीत की। इस दौरान उन्होंने देश के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की तेजी से बढ़ती क्षमता की सराहना करते हुए भारत को वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए अधिक सहयोग और नवाचार पर जोर दिया।

इस बैठक में उन स्टेट्स के प्रतिनिधि शामिल हुए जो रॉकेट निर्माण, पुनः उपयोग योग्य अथवा क्रायोजेनिक प्रक्षेपण यान, उपग्रह तकनीक, वैमानिकी इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्नत प्रणोदन प्रणाली, अंतरिक्ष एवं रक्षा खुफिया समाधान, अंतरिक्ष मलबा हटाने की तकनीक तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-आधारित मौसम और जलवायु पूर्वानुमान जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

स्टार्टअप संस्थापकों ने प्रधानमंत्री को भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में हुई तेज प्रगति के बारे में जानकारी दी और भविष्य के लिए अपनी योजनाएं साझा कीं। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनियों ने स्पेसशिप तकनीक और क्षमताओं के विकास में वर्षों की मेहनत और निवेश किया है। साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र को

निजी भागीदारी के लिए खोलने और विभिन्न नीतिगत सुधारों के लिए केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री का आभाष भी व्यक्त किया। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार के सहयोग और कंपनियों के बीच बढ़ती भागीदारी के कारण एक मजबूत अंतरिक्ष पारिस्स्थितिकी तंत्र विकसित हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी टीमें बड़े व्यक्त्यों को हासिल करने के लिए उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं। स्टार्टअप प्रमुखों ने यह किया कि जब सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी सहभागिता के लिए खोला था, तब इससे उद्योग जगत में नया उत्साह पैदा हुआ और भारतीय कंपनियों के लिए अनेक अवसर खुले। उन्होंने यह भी बताया कि अब कई उद्योग और संस्थान निजी अंतरिक्ष कंपनियों द्वारा

विकसित तकनीकों को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप संस्थापकों के साहस, नवाचार और पहल की सराहना करते हुए कहा कि निजी कंपनियों द्वारा प्रदर्शित आत्मविश्वास ने अंतरिक्ष क्षेत्र को उदारीकृत करने के निर्णय को और मजबूत किया है।

उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों के पास अंतरिक्ष कार्यक्रमों में बड़े निवेश करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं या वे ऐसे निवेश को प्राथमिकता नहीं देते। ऐसी स्थिति भारत के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है, जिससे वह वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में अपनी स्थिति को तेजी से मजबूत कर सकता है।

प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र की कंपनियों को अपनी तकनीकों के नए

उपयोग तलाशने और ऐसे समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित किया जो आम लोगों के जीवन को आसान बना सकें। उन्होंने अंतरिक्ष स्टार्टअप और अन्य क्षेत्रों में काम कर रही कंपनियों के बीच अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

प्रथममंत्री ने सुझाव दिया कि अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन पर काम करने वाली कंपनियों पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं के साथ साझेदारी कर सकती हैं, ताकि उनको तकनीक का व्यापक उपयोग हो सके। इसी तरह कृषि क्षेत्र से जुड़ी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की संकायों कृषि विश्वविद्यालयों और सरकारी विभागों के साथ मिलकर किसानों को बेहतर निर्णय लेने, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।

कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय उत्तर प्रदेश सरकार की सम्पत्ति है। नृपेन्द्र मिश्र ने सोचा कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी एक संग्रहालय बनाना है। छोटे से करके में दो संग्रहालय व्यवहारिक नहीं हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने स्वीकार कर लिया।

उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में लिखित अनुबंध हुआ। 30 वर्ष के लिए संग्रहालय भवन की क्षेत्र ट्रस्ट को लीज पर प्राप्त हो गया। उसे देखने पर सब ने अनुभव किया कि इसका पूर्ण जीर्णोद्धार आवश्यक है। वृषेन्द्र मिश्र ने संग्रहालय के सम्पूर्ण कार्य की देखभाल के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय से सेवा निवृत्त सजीव सिंह का चयन किया। वे अयोध्या आए गए। सभी कार्य संभाल लिया।

राय के अनुसार, वास्तुकार जयकाकावीर ने झुंडंग बनाई। उत्त प्रदेश राजकीय निर्माण निगम कं सौंपा गया कार्यो दिया। ईंजीनियर इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) कं सौंपा गया। कार्यो के सुधाराल का कार्य सौंपा गया। संजीब सिंह ने संग्रहालय मे 20 गैरुरी कं रूपरेखा तैयार की। दूसरे के अध्यक्ष मिश्र ने कुछ कार्यो कं विकसित करने और संग्रहालय मे लगाने का कार्य आइ.आई. टी. मद्रास को सौंपा दिया। उन्होंने आध्यात्मिक अरु देखा और कार्य प्रारम्भकर दिया। प्रति मास मंदि निर्माण समिति की बैठक के साथ-साथ संग्रहालय से संबंधित कार्यो के लिए हं दे-तीन सत्रों मे नुपेन्द्र मिश्र ने संबंधित सभी व्यक्तियों के साथ बैठना प्रारम्भ कर दिया। धीरे-धीरे कार्य आगे बढ़ रहा है। संग्रहावन है कि दिसम्बर 2027 तक संग्रहालय समाज को देखने के लिए खोल दिया जाणु।

**पूरा 'वन्दे मातरम्' गाया जाना इस बार
स्वतंत्रता दिवस को खास बना गया : शाह**

सिलीगुड़ी, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि देश की आजादी और विभाजन के बाद लंबे समय तक कुछ लोगों ने 'वंदी मातरम्' को पूरे मन से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि संसद में इस गीत को गाया जाता था और सभी लोग सम्मान में खड़े होते थे, लेकिन आजादी के बाद भी इसका पूरा संस्करण नहीं गाया जाना उन्हें हमेशा खलता रहा।



चंद्रोपाध्याय ने अपनी रचना के माध्यम

अमित शाह ने यह बात दाजिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के अधिकारियों और जवानों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने जवानों से संवाद किया और सिलीगुड़ी में कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का समारोह उनके लिए खास रहा। शाह ने बताया कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब भी लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, वह वहां मौजूद रहे हैं। लेकिन इस बार 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अलग रहा, क्योंकि पहली बार पूरा 'वंदे मातरम्' गाया गया।

गृह मंत्री ने 'वंदे मातरम्' की रचना करने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को याद करते हुए कहा कि इस रचना ने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी, बल्कि स्वतंत्र भारत की कल्पना को भी दिशा दी। उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र

चूटोपाध्याय ने अपनी रचना के माध्यम से यह बातों का प्रयास किया कि स्वतंत्र भारत कैसा होगा चाहिए।

सीमा सुरक्षा और सीमा पर बाधा लगाने के लिए जमीन आवंटन के मुद्दे पर अमित शाह ने मुख्यमंत्री शुभेन्द्र आँकवारों की सलाहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पद संभालने के बाद सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए जमीन आवंटन का लंबे समय से लंबित काम तेजी से आगे बढ़ा है। राज्य सरकार अब तक इसके लिए 1,129 एकड़ जमीन आवंटित कर चुकी है।

अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार उनसे उलपल व झगड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराया का आग्रह किया था, लेकिन उनका अपील पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में भाजपा के लिए नहीं, बल्कि देश की सीमा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जमीन मांग रही थी।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भारत दौरा: राष्ट्रपति भवन में पूर्ण अभ्यास की तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति भवन ने शुक्रवार को संकेत दिया कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिका रहमान की आगामी भारत यात्रा तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। उनके औपचारिक स्वागत की तैयारियों के तहत राष्ट्रपति भवन ने साप्ताहिक 'चेंज ऑफ गार्ड' समारोह को रद्द करने की घोषणा की है ताकि स्वागत समारोह का पूरा अभ्यास किया जा सके। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाले 'चेंज ऑफ गार्ड' समारोह (सुरक्षा गार्ड को बदले जाने से जुड़ा एक सैन्य कार्यक्रम) इस शनिवार (22 अगस्त, 2026) को नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के औपचारिक स्वागत के लिए पूर्ण अभ्यास किया जाना है।

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब 12-13 सितंबर को होने वाले 'ब्रिक्स' के शिखर सम्मेलन के लिए रहमान की प्रस्तावित नई दिल्ली यात्रा को लेकर राजनयिक अनिश्चितता बनी

हुई है। यह अनिश्चितता दोनों पड़ोसी देशों के बीच हालिया तनाव के कारण है, जो ढाका की ओर से अपरत्य प्रचाराप्रेमी शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग किए जाने से पैदा हुई है। इससे पहले मंगलवार को, भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में बांग्लादेशी व्यापारिक नेताओं और भारत से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रहमान की यात्रा की 'यादगार' बनाना चाहते हैं।

त्रिवेदी ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने बस एक बात कही है। हमें मिलना चाहिए। हालाँकि, ढाका की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रहे हैं। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस की बुरहस्पतिवार को दिए गए एक साक्षात्कार में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार हुमायूँ कबीर ने कहा था कि जब तक 'आपसी भरोसे' का माहौल नहीं बन जाता और नई दिल्ली की ओर से 'स्वाम्यन जनक आमंत्रण' नहीं मिलता, तब तक रहमान के शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावना 'बहुत कम' है।

प्रमोद द्विवेदी
9415646927
9559933018



राजेश तिवारी (मैनेजर)
9454392110
9450408942

डीलर : हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, जे.के. टायर एवं अपोलो टायर

उत्कर्ष आटोमोबाइल्स

कुण्डाडीह, स्योरपुर, सोनभद्र

सम्पादकीय

पुलिस दमन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

जंतर-मंतर पर २० जुलाई को छात्रों के हक की मांग उठा रहे प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस ने जो अत्याचार पर किया है, उसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जोयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज, किसी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। पीठ ने कहा कि इस उच्चस्तरीय पैनल को मामले के तथ्य जुटाने का काम सौंपा जाएगा और इसे समय-समय पर अपनी रिपोर्ट देनी होगी, जिसके आधार पर न्यायालय आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों के साथ यौन उत्पीड़न, ऑनलाइन उत्पीड़न (साइबर बुलिंग) और सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील/कमजोर वर्ग के लोगों को निशाना बनाए जाने के आरोपों की भी जांच करेगी।

शीर्ष अदालत के इस फैसले से यह तो स्पष्ट हो चुका है कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर दमनकारी उपार आजमाए गए थे। हालांकि २० जुलाई के सैकड़ों-हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिनमें नजर आ रहा है कि प्रदर्शनकारियों को मारा-पीटा गया। पीटने वालों में पुलिस की वर्दी पहने लोग भी हैं, जिनमें कईयों की वर्दी पर कोई नाम नहीं है, वहीं कुछ लोग सादे कपड़ों में भी पीटते हुए दिखे। किसी लड़की को पुरुष पुलिसकर्मों ने पीटा तो किसी तिरंगा पकड़े हुए लड़के को पुलिस ने उठा कर पटक दिया, जिससे उसके हाथों से तिरंगा भी जमीन पर गिरा। राहुल गांधी ने तो प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्ण तरीके से पैलेट गन के इस्तेमाल का भी न केवल आरोप लगाया, बल्कि उससे घायल लोगों को मीडिया के सामने प्रस्तुत भी किया। सरकारी अस्पतालों की भी रिपोर्ट आई है कि कम से कम १० मरीज ऐसे आए जो पैलेट गन से घायल हुए हैं।

विपक्ष दलों ने सरकार से इसी पर जवाब मांगा कि प्रदर्शनकारियों पर ऐसे भयावह दमन की इजाजत किसने दी। लोकतंत्र के सबसे बड़े स्थल संसद में बाकायदा सरकार से सवाल पूछा गया, लेकिन जवाब देने की जगह गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में आना ही जरूरी नहीं समझा। इधर मौलानावार को ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस का बचाव करते हुए कहा कि इतने बड़े आंदोलन के बावजूद किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, किसी की एक हड्डी नहीं टूटी और किसी प्रदर्शनकारी को गंभीर चोट नहीं लगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन का पैमाना बड़ा था और इस्में कथित तौर पर कुछ 'अपराधी' भी छात्रों के रूप में शामिल हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी, "डफली बजाने वाले प्रदर्शनकारियों", भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी से जुड़े कई लोग आंदोलन में आए और उन्होंने लोगों को भड़काया। इसके बाद भाजपा शासन के चिर-परिचित अंदाज में किरण रिजिजू ने कांग्रेस की गलती बताते हुए कहा कि उस के शासनकाल में कई आंदोलनों में हजारों लोगों की मौत हुई थी। उनके

छड़खणियों से

– डॉ. प्रियंका सौरभ

स्कूल केवल पढ़ाई की जगह नहीं होते। वे बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण, संस्कार, अनुशासन और सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं। माता-पिता जब अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं तो उनके मन में यह विश्वास होता है कि शिक्षक उनके बच्चे को ज्ञान देने के साथ-साथ उसकी सुरक्षा और गरिमा का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जब इसी भरोसे की आड़ में किसी शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ छेड़खानी, अनुचित व्यवहार या यौन उत्पीड़न की घटना सामने आती है, तो चोट केवल एक बच्ची को नहीं लगती; पूरा शैक्षणिक तंत्र कटघरे में खड़ा हो जाता है।

विद्यालयों में छात्राओं के साथ शिक्षकों द्वारा अनुचित व्यवहार की खबरें समय-समय पर सामने आती रही हैं। हर घटना की प्रकृति और तथ्य अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर दोषी ठहराना उचित नहीं है। लेकिन शिकायत सामने आने के बाद उसे दबा देना, बच्ची को चुप कराने की कोशिश करना या संस्थान की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मामले को टालना उससे भी अधिक गंभीर समस्या है। किसी भी विद्यालय की प्रतिष्ठा बच्चों की सुरक्षा से बड़ी नहीं हो सकती।

शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता मूलतः विश्वास पर आधारित होता है। एक शिक्षक के पास ज्ञान के साथ-साथ अधिकार भी होता है। छात्र शिक्षक की बात को स्वाभाविक रूप से महत्व देता है और कई बार उसे अपने माता-पिता के बाद सबसे विश्वसनीय वयस्क मानता है। यही कारण है कि यदि कोई शिक्षक इस विश्वास और अधिकार का दुरुपयोग करता है तो बच्ची के लिए विरोध करना आसान नहीं होता। किशोरावस्था में बच्चे कई बार यह समझ ही नहीं पाते कि किसी वयस्क का व्यवहार सामान्य है या अनुचित। डर, शर्म, सामाजिक दबाव, परीक्षा और भविष्य को लेकर चिंता तथा यह भय कि उनकी बात पर विश्वास किया जाएगा या नहीं—उन्हें शिकायत करने से रोक सकते हैं। इसलिए केवल यह पूछना कि बच्ची ने पहले शिकायत क्यों नहीं की? पर्याप्त नहीं है। असली सवाल यह होना चाहिए कि क्या विद्यालय ने ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाया है जिसमें बच्ची बिना डर अपनी बात कह सके?

ऐसे मामलों में सबसे खतरनाक तत्व अक्सर चुपची होती है। कई परिवार सामाजिक बदनामी के डर से शिकायत नहीं करना चाहते। कुछ लोग यह सोचकर मामले को दबा देते हैं कि बच्ची की पढ़ाई प्रभावित होगी। विद्यालय प्रशासन भी कभी-कभी संस्थान की छवि खराब होने की चिंता में शिकायत को आंतरिक स्तर पर समाप्त करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ऐसी चुपची गलत व्यवहार को बढ़ावा दे सकती है। यदि किसी बच्ची की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो उसे यह संदेश मिल सकता है कि उसकी सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण संस्थान की प्रतिष्ठा है। यह संदेश किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहद चिंताजनक है। इसलिए अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन को यह समझना होगा कि शिकायत करना बदनामी नहीं, बल्कि सुरक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है। आरोप की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर कानून तथा संस्थागत नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यालय प्रशासन की भूमिका केवल घटना होने के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सुरक्षा की व्यवस्था पहले से मजबूत होनी चाहिए। शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के दौरान उचित सत्यापन, स्पष्ट आचार-संहिता, विद्यार्थियों के साथ व्यवहार के नियम तथा शिकायत की सुरक्षित व्यवस्था आवश्यक हैं।

विद्यालयों में बच्चों को यह बताया जाना चाहिए कि अच्छा और अनुचित स्पर्श क्या होता है, असहज व्यवहार की पहचान कैसे करें और किसी विश्वसनीय वयस्क को इसकी जानकारी कैसे दें। यह शिक्षा केवल छात्राओं के लिए नहीं, बल्कि सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए। उन्हें यह भी समझाया जाना चाहिए कि किसी भी अनुचित व्यवहार के लिए वे स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं। स्कूलों में ऐसी शिकायत व्यवस्था होनी चाहिए जहां बच्चा बिना भय के अपनी बात रख सके। महिला शिक्षक, प्रशिक्षित काउंसलर या अन्य विश्वसनीय वयस्क की उपलब्धता इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है।

भारत में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने के लिए POCSO Act, २०१२ मौजूद है। १८ वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ यौन अपराधों के मामलों में यह कानून महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। विद्यालयों और उनके कर्मचारियों को इस कानून की मूलभूत जानकारी होना आवश्यक है। किसी गंभीर शिकायत को केवल ‘विद्यालय का

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

पिछले दिनों पंद्रह अगस्त के

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में

से नक्सल आतंक को समाप्त

कर दिया गया है, लेकिन कुछ

दिमागी नक्सल अभी भी बचे

हुए हैं। इसको लेकर बहुत हो

हल्ला हुआ। कुछ लोग बहुत

ज्यादा गुस्से में आ गए। लेकिन

गुस्से में आने वालों को एक ही

तराजू पर नहीं तोला जा

सकता। उनमें से कुछ तो ऐसे

हैं जो सचमुच ही दिमागी

नक्सलवादी हैं। वे अभी तक

चुपचाप अपना काम कर रहे

थे। उनके इस ‘चुपचाप काम’

का खामियाजा पूरा देश भुगत

रहा था, लेकिन इन छिपे

दिमागी नक्सलवादियों की

किसी को भनक तक नहीं लग

रही थी। जैसे कोई शांतिर चोर

अचानक चोरी करता हुआ

पकड़ा जाए तो वह समय की

नजाकत को भांप कर

राबिनहुड बनने की कोशिश

करता है। इस प्रथम कैटेगरी में

पी. चिंदंबरम आते हैं।



राजेश पांडेय

शिक्षा का सीधा संबंध रोजगार से है। असंतोष और संकट के मूल में बढ़ती बेरोजगारी है। हर साल वर्क फोर्स में ७०-८० लाख युवा जुड़ते हैं। ८०प्रतिशत बेरोजगार १५ से २४ आयु वर्ग के हैं। ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दर २९ फीसदी के आसपास है। आंदोलनों की अगली कतार में इस आयु वर्ग के लोग अधिक हैं। स्कूली छात्रों के जुड़ने का कारण अनिश्चित भविष्य तो है ही।

२० जुन को जंतर-मंतर, नई दिल्ली के शुरू हुए छात्रों के आंदोलन की आवाज देश के कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश,राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश सहित कई राज्यों में विद्यार्थियों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया और रैलियां निकाली हैं। कहीं बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, स्कूलों में शिक्षकों और जरूरी सुविधाओं की कमी, तो कहीं होस्टल की ज्यादा फीस जैसे मुद्दों ने छात्रों को सड़क पर आने के लिए प्रेरित किया है। बदलाव और बेचैनी की ऊर्जा से भरी यह हलचल हमारे समाज, राजनीति और सरकारी तंत्र को वर्तमान दौर की चुनौतियों को समझने और उसके हिसाब से कदम उठाने का स्पष्ट संदेश देती है।

इन आंदोलनों ने कुछ अहम पहलुओं को रेखांकित किया है। कुछ नए ट्रेंड उभर

डॉ. ज्ञान पाठक

आलोचनाओं में से एक यह थी कि जो फंड जनता का पैसा स्वीकार करता है-जिसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) योगदान और दूसरों से दान शामिल है - उसे पब्लिक ऑडिट के दायरे से बाहर क्यों रखा जाए, जबकि इस निजी फंड को एक सरकारी संस्था जैसा दिखाया जाता है। आलोचकों का तर्क था कि यह बेईमानी थी।

यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि मार्च २०२० में कोविड-१९ संकट के दौरान अपनी सार्वजनिक छवि को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 'पीएम केयर्स' नाम का प्रचार-प्रसार वाला शब्द गढ़ा था, ताकि लोगों को बताया जा सके कि वह लोगों का ध्यान रखते हैं। इस शब्दावली को विस्तारित कर इसका नाम रखा गया 'प्राइम मिनिस्टर्स सिटिजन एसिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमर्जेंसी सिचुएशन' (आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और राहत) रखा गया और इसे २७ मार्च २०२० को लॉन्च किया गया, ठीक २४ मार्च २०२० की शाम को लॉकडाउन की घोषणा के बाद। विपक्ष का आरोप था कि इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अलग इसलिए बनाया गया था ताकि फंड की सार्वजनिक जांच से बचा जा सके। अब छह साल बाद हमें एहसास हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसीबत में फंसे

दिमागी नक्सल को लेकर नई बहस

तब तुरंत कांग्रेस में घुसे हुए पी. चिंदंबरम जैसे दिमागी नक्सलवादियों ने समझ लिया कि इस चेतावनी की गंभीरता को कम करने के लिए चिल्लाया जाए कि हां में दिमागी नक्सल हूं। महबूबा मुफ्ती जैसे लोग देखादेखी चिल्ला रहे हैं कि शायद यह तगमा भी शोहरत देगा। लेकिन कांग्रेस को गंभीरता से अपने यहां से दिमागी नक्सलियों को निकालना चाहिए। पर क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि कहा जाता है कि राहुल गांधी को भी पार्टी ने दिमागी नक्सलियों ने ही घेरा हुआ है।

पिछले दिनों पंद्रह अगस्त के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में से नक्सल आतंक को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन कुछ दिमागी नक्सल अभी भी बचे हुए हैं। इसको लेकर बहुत हो हल्ला हुआ। कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। लेकिन गुस्से में आने वालों को एक ही तराजू पर नहीं तोला जा सकता। उनमें से कुछ तो ऐसा हैं जो सचमुच ही दिमागी नक्सलवादी हैं। वे अभी तक चुपचाप अपना काम कर रहे थे। उनके इस ‘चुपचाप काम’ का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा था, लेकिन इन छिपे दिमागी नक्सलवादियों की किसी को भनक तक नहीं लग रही थी। जैसे कोई शांतिर चोर अचानक चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो वह समय की नजाकत को भांप कर राबिनहुड बनने की कोशिश करता है। इस प्रथम कैटेगरी में पी. चिंदंबरम आते हैं। दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की है जिसको न नक्सलवाद से कुछ लेना-देना है और न ही उनका इससे कुछ लेना-देना है। क्योंकि मोदी ने कहा है कि कुछ छिपे हुए दिमागी नक्सल अभी भी बचे हुए हैं, इससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि क्योंकि मोदी अपने विरोधी दल वालों को तरह तरह से उकसाते हैं, इसलिए जरूर ये दिमागी नक्सल इंडी गठबंधन में होंगे। अब इंडी गठबंधन में

उनको वह स्थान नहीं मिल रहा जो पहले मिला करता था। ऐसे लोगों को लगा कि इंडी गठबंधन में अपनी खोई हैसियत दोबारा पाने का यह सुनहरी मौका है।

उनको लगा देश की जनता यह मान लेगी कि मोदी से जो विरोधी नेता लड़ सकता है, वह वही है जो इस वक्त ज्यादा चिल्लाएगा कि वह दिमागी नक्सल है। इस कैटेगरी में दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल आते हैं। अभी नरेंद्र मोदी का लाल किला का संबोधन शावाद पूरा भी नहीं हुआ था कि केजरीवाल ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि वह ही सबसे बड़ा दिमागी नक्सलवादी है। केजरीवाल को लगा कि राहुल गांधी जब भी भारत में आते हैं, तो चीख चिल्ला कर बातना शुरू कर देते हैं कि विरोधी पक्ष का मैं ही नेता हूं। मोदी मुझसे उठते हैं। इस प्रकार लड़ाई मोदी बनाम राहुल बनती है। यह देखकर केजरीवाल ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि वह सबसे बड़े दिमागी नक्सलवादी हैं। वैसे भी केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत ही इस मंत्र से की थी। वे रहे थे। उनके इस ‘चुपचाप काम’ का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा था, लेकिन इन छिपे दिमागी नक्सलवादियों की किसी को भनक तक नहीं लग रही थी। जैसे कोई शांतिर चोर अचानक चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो वह समय की नजाकत को भांप कर राबिनहुड बनने की कोशिश करता है। इस प्रथम कैटेगरी में पी. चिंदंबरम आते हैं। दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की है जिसको न नक्सलवाद से कुछ लेना-देना है और न ही उनका इससे कुछ लेना-देना है। क्योंकि मोदी ने कहा है कि कुछ छिपे हुए दिमागी नक्सल अभी भी बचे हुए हैं, इससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि क्योंकि मोदी अपने विरोधी दल वालों को तरह तरह से उकसाते हैं, इसलिए जरूर ये दिमागी नक्सल इंडी गठबंधन में होंगे। अब इंडी गठबंधन में

छात्रों ने कई मुद्दों पर बुनियादी बदलाव का मैसेज दिया

रहे हैं। छात्रों के आंदोलन राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहे। आमतौर पर किसी मुद्दे, मांग या विषय के पक्ष-विपक्ष में जनता के विभिन्न वर्ग बड़े शहरों में एकजुट होते आए हैं। अक्सर राजनीतिक दलों, छात्रों, मजदूर संघों और सामाजिक संगठनों द्वारा जनमत जगाने, विरोध जनाने और लोगों को संगठित करने की मुहिम राजधानियों या बड़े शहरों में आकार लेती है। बहुत व्यापक आंदोलनों को छोड़ दें तो कई बार वह उन्हीं स्थानों तक सिमटकर रह जाती है। इस बार जैसी राजधानियों से उठी आवाज की अनुमृत्ति छोटे शहरों में सुनाई पड़ रही है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले लोगों के स्वरूप में हुआ है। कलेज छात्रों के साथ स्कूली छात्र आगे आए हैं। स्कूली छात्र सिर्फ हाईस्कूल तक सीमित नहीं हैं। कई शहरों में आकार लेती हैं। खयाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? जाहिर है, वे मौजूदा स्थितियों में अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं हैं। उन्हें जंदगी की दौड़ में पिछड़ने का खतरा नजर आता होगा।

छोटे शहरों के छात्रों के जागरूक होने का मुख्य कारण उनकी मांग तो है ही पर सोशल मीडिया ने उनके लिए कंटैलिस्ट या उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। मोबाइल के

डॉ. ज्ञान पाठक

लोगों की मदद करने के बजाय दान का पैसा बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना ज्यादा संपद था।

इसका एक बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब २०२४-२५ के लिए पीएम केयर्स फंड का ऑडिट स्टेटमेंट सार्वजनिक किया गया। ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के दौरान पीएम केयर्स फंड को कुल १२७९.९ करोड़ रुपये मिले, लेकिन उसने केवल ८७.८५ लाख रुपये खर्च किए। पीएम केयर्स फंड के पास कुल ८,५४२ करोड़ रुपये उपलब्ध थे, जिसमें से ७,८४७ करोड़ रुपये (लगभग ९३ प्रतिशत) बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे गए थे, जबकि ६०५ करोड़ रुपये सेविंग्स अकाउंट में रखे गए थे। यह स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता को दर्शाता है, जिन्होंने देश के लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री लोगों की परवाह करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही लगती है।

जब से पीएम केयर्स फंड की स्थापना हुई, यह मुख्य रूप से एक ट्रस्ट के तहत निजी फंड के रूप में स्थापित होने के कारण विवादों में रहा, हालांकि इसमें सार्वजनिक जांच से बचा जा सके। अब छह साल बाद हमें एहसास हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसीबत में फंसे

परदे का छोट्टा स्क्रीन उन्हें दिल्ली से लेकर सैनफ्रांसिस्को तक की हलचल के प्रति जानकारी देता है। वे सिर्फ रील बनाने, देखने या मनोरंजन तक सीमित नहीं होंगे। उन्हें साइंस, टेक्नालॉजी, इनोवेशन से जुड़ी गतिविधियों की खबरें मिल रही हैं। स्पेस साइंस के चमत्कार की उनकी कल्पनाओं का हिस्सा बन रहे होंगे। वे देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका के कोई मार्क जकरबर्ग फेसबुक, न्हाटथरण जैसा टूल बनाते हैं तो कैसे ओपन एआई के सैम आल्मैनन चैट जीपीटी पेश कर रहे हैं। वे यह भी जानने लगे हैं किस तरह मेडिकल साइंस ने दिल और मस्तिष्क के रोगों सहित कई लाइलाज बीमारियों में राहत देने का रास्ता खोज लिया है। सूचना क्रांति का वर्तमान समय छात्रों सहित हर किसी को लोकतंत्र, आजादी और खुलेपन की अवधारणा बताता है। वह उनके अंदर सिस्टम की जड़ता को तोड़ने और नई राह पर चलने की बेचैनी पैदा करता है। उन्हें कहीं लगता है कि वे असली बदलाव से बहुत दूर हैं। युवा महसूस कर रहे हैं कि मौजूदा व्यवस्था उन्हें सिर्फ प्रतियोगिता की अंतहीन होड़ में झोंक रही है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था को नैतिकता, ईमानदारी, विश्वसनीयता और मानवीय मूल्यों के प्रसार का वाहक होना चाहिए। लेकिन इसका उच्छा हो रहा है। हम हर कहीं मूल्यों का क्षरण देखते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा अपने पुराने ढर्रे पर चल रहा है। ऐसे सिस्टम से युवाओं का मोहभंग और हताशा स्वाभाविक है। आधुनिक दौर में ऐसी

'पीएम केयर्स' फंड का ऑडिट

भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम भी शामिल था। ऐसा स्पष्ट रूप से कैम ऑडिट से बचने और आरटीआई अधिनियम के तहत जनता को जानकारी देने से रोकने के लिए किया गया था। इसे एक सरकारी संस्था के तौर पर नहीं बनाया गया था, हालांकि भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर दान मांगा और लिया गया था। जमा किए गए फंड का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और फंड के ट्रस्टी अपनी मजी से करते हैं, और यह भारत सरकार के खातों का हिस्सा नहीं होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय नियमित रूप से मिले फंड के इस्तेमाल के बारे में जानकारी नहीं देता है। शुरूआती सालों से लेकत २०२२-२३ तक की ऑडिट रिपोर्ट बहुत देरी से जारी की गई, और दो साल के अंतराल के बाद, वित्तीय वर्ष २०२३-२४ और २०२४-२५ के ऑडिट किए गए स्टेटमेंट १८ अगस्त, २०२६ को सार्वजनिक किए गए। यह फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता की कमी का एक स्पष्ट उदाहरण है, और २०२२-२३ के दो वर्ष बाद भी पब्लिक ऑडिट स्टेटमेंट जारी होने के कारण इसे जनता की आलोचना का सामना करना पड़ा।

आलोचनाओं में से एक यह थी कि जो फंड जनता का पैसा स्वीकार करता है-जिसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी

आखिर दिमागी नक्सलवादी का अर्थ क्या है? अपने वक्त में एक यहूदी कार्ल मार्क्स ने बहस चलाई थी कि संसार को बदलने के लिए, उसमें आम लोगों को शामिल करने और उनकी राय को समझने बूझने की जरूरत नहीं है। संसार को बदलने का, सिस्टम को बदलने का निर्णय चंद गिने नसे लोग ही करते हैं।

यह जरूरी तो नहीं ‘संसार बदल देने’ के उनके इस निर्णय से लोग सहमत ही हों। इसका उत्तर मिल चुका था कि उनकी राय की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वह भी तो हो सकता है कि लोग उनके इस प्रयोग का विरोध ही शुरू कर दें। इसका उत्तर था कि परिवर्तन बंदूक से आता है। इसके लिए चुनाव करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। बैलेट बाक्स नहीं, बल्कि बुलेट इसका फैसला करता है। ऐसे तर्क गढ़ने वाले दिमागी लोग ही होते हैं। रूस में सबसे पहला ऐसा प्रयोग हुआ। परिवर्तन तो हो गया लेकिन उसमें लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। इस नए प्रयोग और सिस्टम को कम्युनिज्म नाम दिया गया। लेकिन साथ ही यूरोप में एक नई बहस भी छिड़ गई कि बंदूक की बजाय लोकतांत्रिक तरीके से भी तो कम्युनिज्म आ ही सकता है। यदि ज्यादा लोग कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दे देंगे तो उसकी सरकार आ जाएगी और नई सरकार परिवर्तन कर ले। भारत में भी १९२५ में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। बाद में उसमें फूट पड़ गया। उसका दूसरा ग्रुप सीपीएम के नाम से काम करने लगा।

सीपीएम ने पश्चिमी बंगाल में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार बना ली और सिस्टम को अपने हिसाब से बदलने का काम करना शुरू कर दिया। तब कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि यह ठीक है कि बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार बना गई है। लेकिन इसका तरीका गलत है। सरकार बदलने का कम्युनिस्ट तरीका तो माओ ने दिखाया है कि ह्मसता बंदूक की गोली से

डॉ. ज्ञान पाठक

व्यवस्था के खिलाफ ताकतवर स्वर उभरते रहे हैं। युवाओं और आम लोगों ने समय-समय पर सत्ता को झकझोरने के लिए अपना असंतोष जाहिर किया है। छात्रों के सत्याग्रह का जिक्र होता है तो मार्च, मई १९६८ में फ्रांस के छात्र आंदोलन को हमेशा याद दिलای जाता है। उस वक्त पेरिस में छात्रों ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में छात्रों की भीड़, शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त साधनों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। देश की ट्रेड यूनियन भी छात्रों के साथ खड़ी हो गई थीं। आंदोलन दूसरे शहरों में फैल गया। मजदूर संघों के साथ आने से कारखानों, दफ्तरों में काम ठप पड़ गया था।

फ्रांस के आंदोलन में तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स डिगाल की दस साल लंबी शक्त का विरोध भी जुड़ा था। डिगाल का शासन अनुदारवादी था। उनकी तानाशाही और मनमानी के खिलाफ नौजवानों और मजदूर वर्ग में असंतोष पनप रहा था। डिगाल ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने नेशनल असेम्बली भंग कर दी। नए चुनाव कराए। देश में फैली अस्थिरता से परेशान मध्यम वर्ग ने डिगाल का समर्थन किया। उनकी पार्टी को संसद में फिर बहुमत मिल गया। १९६९ में डिगाल ने संसद के स्वरूप में बदलाव के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया। लेकिन जनमतसंग्रह में हारने पर अग्रैल में उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया।

भारत में विभिन्न स्तरों पर चल रही छात्रों की हलचल का संबंध व्यवस्था, विरोधी भी है। निश्चित रूप से वह स्कूल,

निकलती हैहैह। लेकिन यहां तो सत्ता वोटों के डिब्बे से निकली थी। यह गलत तरीका है। सही तरीके से सत्ता परिवर्तन होना चाहिए था। उन्होंने अपना तीसरा ग्रुप बना लिया जिसका नाककरण हुआ सीपीआई (एमएल), यानी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी। इस पार्टी ने बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से परिवर्तन का कम्युनिस्ट तरीका प्रयोग करना शुरू किया और गोली मार कर लोगों की जमीनों पर कब्जा शुरू किया। यह पार्टी नक्सलवादी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस पार्टी ने एक नया नारा भी दिया कि ‘चीनर चेयरमैन आमादर चेयरमैन’, यानी चीन का चेयरमैन ही हमारा अर्थात भारत का चेयरमैन है। इस पार्टी ने अपने विभिन्न गुटों में तालमेल बिठा कर भारत के विभिन्न प्रांतों के लगभग १८० जिलों में अपना सिस्टम कायम कर लिया था और इसको लाल गलियारा कहा जाने लगा। इस पूरी प्रक्रिया के दो हिस्से थे। कुछ लोग शहरों में बैठ कर नौजवानों को परिवर्तन के सही माओवादी तरीके समझाते थे। ये नौजवान जंगलों में जाकर बंदूक की गोली से परिवर्तन लाने में जुड़ते थे, मारे जाते थे और शहरों में बैठे दूसरे लोग नई खेप तैयार करते रहते थे। इस पूरी प्रक्रिया में अब तक लाखों लोग मारे गए। शहरों में बैठ कर मौत का यह धंधा करने वालों को दिमागी नक्सल कहा जाने लगा।

दिमागी नक्सलवादियों ने भी दोहरी रणनीति अपनाई। उनमें से बहुत से समय-समय पर कांग्रेस पार्टी में घुस गए। पार्टी का मानना था कि कांग्रेस की अपनी यह विचारधारा तो नहीं है। इसलिए कांग्रेस में घुस कर इसके आल्ट्रेस पर ही कब्जा कर लेना चाहिए। मोदी ने इसी का खुलासा किया था कि जंगल में बंदूक से लोगों को मारने वाले नक्सल तो समाप्त हो गए हैं, अब केवल दिमागी नक्सल बचे हैं, उनसे होशियार रहने की जरूरत है।

डॉ. ज्ञान पाठक

कॉलेजों में साधनों के अभाव से जुड़ा है। शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारों का खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के २.८ से ४.३ प्रतिशत के बीच चल रहा है। वैसे, राष्ट्रीय नीति में शिक्षा पर जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने की नीति रही है। लेकिन सरकारें इसका पालन नहीं कर रही हैं। संविधान की सप्तमवीं सूची में शिक्षा राज्यों का विषय है। इसलिए राज्यों के हिस्से में शिक्षा के खर्च का हिस्सा ७५ प्रतिशत और केंद्र सरकार का २५ प्रतिशत है। शिक्षा की पहली सीढ़ी स्कूल हैं। इसलिए उसके खर्च में कमी का असर भविष्य में शिक्षा के प्रसार और उसके स्तर पर पड़ता है। अपर्याप्त बजट का नतीजा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, शाला भवनों की दुर्दशा और अन्य सुविधाओं के अभाव में सामने आया है। विशेष रूप से छोटे शहरों और दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के स्कूल ज्यादा अभावग्रस्त हैं। शिक्षा के प्रति सरकारों की उपेक्षा को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर कर सकते हैं। देश में २०१४-१५ से २०२४-२५ के बीच सरकारी स्कूलों की संख्या ९४ हजार कम हुई है। इसमें उन स्कूलों की संख्या शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकारों किसी अन्य स्कूल में शामिल करती हैं। अच्छी बात यह है कि इस दरम्यान शिक्षकों की संख्या में ११ लाख से अधिक इजाफा हुआ है। इन स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या दो करोड़ २६ लाख कम हो गई थी। सरकारी स्कूलों की घटती संख्या और साधनों का अभाव शिक्षा के प्रति सरकारों की प्राथमिकता का प्रमाण है।

डॉ. ज्ञान पाठक

करोड़ रुपये खर्च किए। २०२२-२३ में इसे १,३०५.९ करोड़ रुपये मिले लेकिन इसने सिर्फ ४३७.९ करोड़ रुपये खर्च किए; २०२३-२४ में इसे ९०४.९ करोड़ रुपये मिले लेकिन इसने सिर्फ १५.६ करोड़ रुपये खर्च किए; और २०२४-२५ में इसे १,२७९.९ करोड़ रुपये मिले लेकिन इसने सिर्फ ०.९ करोड़ रुपये खर्च किए। कुल मिलाकर, मार्च २०२० में शुरू होने से लेकर ३१ मार्च २०२५ तक, इस फंड ने अपनी कुल कमाई का पांचवें हिस्से से भी कम- यानी सिर्फ १८.४ प्रतिशत - खर्च किया है। वित्त वर्ष २०२४-२५ में इसने अपने क्लोजिंग फंड का सिर्फ ०.०१ प्रतिशत खर्च किया।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि फंड का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, जबकि बड़ी संख्या में लोग प्राकृतिक और इंसानी आगदाओं के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। आपातकालीन स्थितियों में जरूरतमंदों की मदद के नाम पर मिले फंड का ९३ प्रतिशत बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर जमा करती नैतिक या मानवीय रूप से सही नहीं लगता। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री देश के लोगों की कितनी परवाह करते हैं और बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे लोगों को राहत देने के नाम पर बैंक डिपॉजिट बढ़ाने में उनकी कितनी दिलचस्पी है।



नयनतारा ने गीतू मोहनदास के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा किया

साउथ सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर गोन-अप्स' को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है। फिल्म में कन्नड़ सुपरस्टार यश मुख्य भूमिका में हैं, जबकि नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुविमणी वसंत और हुमा कुरेशी जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। फिल्म को लेकर चर्चा सिर्फ इसकी स्टारकास्ट और कहानी की वजह से नहीं है, बल्कि निर्देशक गीतू मोहनदास के काम करने के तरीके ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। अब फिल्म की अभिनेत्री नयनतारा ने गीतू की तारीफ की है। हाल ही में 'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में नयनतारा ने गीतू मोहनदास के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा, 'अब तक सभी लोग गीतू की एक निर्देशक के तौर पर खूब तारीफ कर चुके हैं, लेकिन मैं उनके व्यक्तित्व के उस पहलू के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो शायद पर्दे के पीछे नजर आता है। गीतू सिर्फ कलाकारों से उनका काम नहीं करवाती, बल्कि उनकी भावनाओं को समझती हैं

और मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी भी रहती हैं।' अभिनेत्री ने आगे कहा, 'फिल्म की शूटिंग के दौरान कलाकारों को कई तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। किसी के लिए दिन अच्छा रहा तो किसी को मुश्किल सेशन का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में गीतू ने निर्देशक होने के साथ-साथ एक मजबूत सहारे की भूमिका भी निभाई। वह हर स्थिति में उनके साथ मौजूद रही। यही चीज गीतू को एक अलग तरह की निर्देशक बनाती है। वह अपने कलाकारों को केवल फिल्म का हिस्सा नहीं मानती, बल्कि उनके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव भी बनाती हैं।' इस दौरान नयनतारा ने फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक भावुक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया, 'एक बार शूटिंग के दौरान गीतू एक कलाकार को लेकर काफी भावुक हो गई थीं। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाईं। इसके बाद वह उस कलाकार के साथ कुछ देर तक रही, ताकि उसे अकेला न महसूस हो।' उन्होंने आगे बताया कि जब गीतू से वापस आईं, तो हमने उनसे पूछा कि

आखिर वहां क्या हुआ था। मुझे लगा कि शायद गीतू ने भावनाओं में आकर कुछ ऐसा कह दिया होगा, जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। मैंने उनसे पूछा, 'क्या हुआ? क्या आपने अपना आपा खो दिया? क्या आपने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको नहीं कहना चाहिए था?' लेकिन गीतू ने बेहद सहजता से कहा, 'नहीं, मैंने बस प्यार दिया।' नयनतारा ने कहा कि गीतू जिस भी कलाकार के साथ काम करती हैं, उसके साथ एक खास रिश्ता बना

लेती हैं। बता दें कि 'टॉक्सिक' का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है और इसकी कहानी यश और गीतू मोहनदास ने मिलकर लिखी है। फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुविमणी वसंत और हुमा कुरेशी नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग कन्नड़ और अंग्रेजी में की गई है और इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम समेत कई भाषाओं में डब किया गया है। केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बनी यह फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।



आत्मविश्वास को लेकर बोलीं ईशा कोपिकर

स्टाइलिश दिखने का उम्र से लेना-देना नहीं

बढ़ती उम्र को लेकर अब लोगों की सोच बदल रही है। खासकर अभिनेत्रियां अपने अनुभवों के साथ यह बताती नजर आती हैं कि उम्र किसी की खूबसूरती, आत्मविश्वास या पहचान तय नहीं करती। अभिनेत्री ईशा कोपिकर भी इसी सोच को लेकर अपनी बात सामने रखती रही हैं। इस कड़ी में उन्होंने सोशल मीडिया पर बेहतरीन तस्वीरों के साथ एक कैप्शन लिखा है।

पहले से ज्यादा बेबाक हुईं

अभिनेत्री ने जो तस्वीरें शेयर की हैं। उस पर अलग-अलग कैप्शन लिखा है। तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने लिखा 'अब मैं पहले से थोड़ी ज्यादा आत्मविश्वासी, अपनी पसंद को लेकर ज्यादा सजग और खुद को लेकर पहले से ज्यादा बेबाक हूँ। असली खूबसूरती और अंदाज उम्र में नहीं, बल्कि इस बात में है कि इंसान समय के

साथ खुद को कितना बेहतर बनाता है।' जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं

ईशा ने आगे लिखा 'मैं अब बेहतर चुनाव करती हूँ, गहराई से प्यार करती हूँ और जिंदगी के हर पड़ाव को खास बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं वही लड़की हूँ, लेकिन अब मेरे स्टैंडर्ड पहले से बेहतर हैं।'

ईशा कोपिकर का वर्कफ्रंट

साल 2000 में फिल्म 'फिजा' से हिंदी में अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री ईशा हाल ही में फिल्म 'लव यू लोकतंत्र' में नजर आईं। अभय निहलानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कृष्णा अभिषेक, अली असगरी, सपना चौधरी, रवि किशन और मनोज जोशी थे।

पैन इंडिया फिल्म 'स्लम डॉग: 33 टेंपल रोड' में अहम किरदार में नजर आएंगी तब्बू

आयकर अधिकारी के रूप में नजर आएंगी। इस फिल्म में तब्बू के किरदार का नाम गौरी हेगड़े है। गौरी को एक निर्दयी, बेरहम और साहसी महिला के रूप में पेश किया गया है। एक्ट्रेस की शेरार की गई पोस्टर में वह बड़े गंभीर अंदाज में नजर आ रही हैं। फिल्म से शेरार किए एक वीडियो में वह विजय सेतुपति से पूछताछ करती नजर आ रही हैं। इस एक पोस्टर के अलावा तब्बू ने 'स्लम डॉग' की एक विलप भी शेयर की। इसके कैप्शन में अभिनेत्री ने लिखा, 'आप सभी मिलिए गौरी हेगड़े से। जो कि एक दूढ़, निडर और हमेशा अपने सिद्धांतों पर डटी रहने वाली महिला है। इस फिल्म के लिए हैदराबादी बोलने में बहुत मजा आया।' कैप्शन में तब्बू ने फिल्म के निर्देशक पुरी जगन्नाथ का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही प्रोड्यूसर चामी कौर का भी शुक्रिया अदा किया।

'स्लमडॉग 33' के बारे में

फिल्म का निर्देशन पुरी जगन्नाथ ने किया है। वहीं इसे पुरी के साथ मिलकर अभिनेत्री चामी कौर ने भी प्रोड्यूस किया है। फिल्म में विजय सेतुपति एक बहुत ताकतवर और बेबाक किरदार निभाएंगे। यह एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है जिसे पांच भाषाओं तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की कास्ट में विजय और तब्बू के अलावा संयुक्ता, दुनिया विजय, ब्रह्माजी और वीटीवी गणेश भी अहम भूमिकाओं में हैं।



यश राज फिल्म्स हॉरर फिल्म में व निभाएंगे लीड र

यश राज फिल्म्स (वाईआरएफ) पहली बार हॉरर जॉनर में कदम रखने जा रही है। इस फिल्म में अभिनेता वरुण धवन मुख्य भूमिका निभाएंगे, जबकि निर्देशन और पटकथा की जिम्मेदारी 'रॉकेट बॉयज' से चर्चित अभय पन्नू संभालेंगे। फिल्म की शूटिंग इस वर्ष के अंत में शुरू होने की

योजना है और इसे में दुनियाभर के रिलीज किया जा

इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के अनुसार, वाईआरएफ की पहली हॉरर फिल्म के लिए वरुण धवन को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना गया है। सूत्रों का कहना है कि यश राज फिल्म्स ने अब तक लगभग हर प्रमुख जॉनर में फिल्में बनाई हैं, लेकिन हॉरर ऐसा जॉनर था, जिसमें स्टूडियो ने अब तक कदम नहीं रखा था। यह फिल्म उसी दिशा में इच्छा की पहली पेशकश होगी।

सूत्रों के अनुसार, अभय पन्नू के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म को अक्षय विधानी रणनीतिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। 'रॉकेट बॉयज' की सफलता के बाद यह अभय पन्नू की पहली थिएटरिकल फिल्म होगी। इसके साथ ही यह परियोजना नई पीढ़ी के फिल्मकारों को अवसर देने की वाईआरएफ की रणनीति को भी आगे बढ़ाती है। 'सैयारा' की सफलता के बाद आदित्य चोपड़ा के मार्गदर्शन में स्टूडियो मोहित सूरी, समीर सक्सेना और अब अभय पन्नू जैसे निर्देशकों के साथ काम कर रहा है। 'सुई धागा' के बाद यह वरुण धवन की यश राज फिल्म्स के साथ दूसरी फिल्म होगी। इस बार वह स्टूडियो की पहली थिएटरिकल हॉरर फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे।

क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल संग अफेयर की खबरों पर भड़कीं मृणाल

इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में सेलिब्रिटीज की निजी जिंदगी को लेकर अफवाहें फैलना अब एक आम बात हो गई है। लेकिन बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री मृणाल ठाकुर इन झूठी खबरों को चुपचाप सहने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। हाल ही में भारतीय युवा क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के साथ अपना नाम जोड़े जाने पर मृणाल ठाकुर का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने अफवाह फैलाने वालों को जमकर खरी-खोटी सुनाई है। पूरा मामला मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित एक कैफे का है। हाल ही में मृणाल ठाकुर और क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को एक ही कैफे के बाहर अलग-अलग समय पर देखा गया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर दोनों के वीडियो को जोड़कर उनके अफेयर के कयास लगाने शुरू कर दिए। 34 साल की मृणाल ठाकुर और 24 साल के यशस्वी के बीच 10 साल के अंतर को लेकर भी इंटरनेट पर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। जब यह अफवाह हद से ज्यादा बढ़ने लगी, तो अभिनेत्री ने खुद सामने आकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो पर टिप्पणी करते हुए मृणाल ठाकुर ने लिखा, 'भाई थोड़ा रिलेक्स करो... मुझे दिखाओ कि हम एक साथ कहाँ हैं? आप जैसे पढ़े-लिखे लोग इन अफवाहों को सच कैसे मान सकते हैं? देश में क्या कुछ नहीं हो रहा है। जेन-जी से कुछ सीखिए और सही मुद्दों पर वीडियो बनाइए, ताकि आपको ज्यादा व्युंज मिल सके।' हालांकि, कुछ समय बाद यह कमेंट वीडियो के नीचे से हटा दिया गया, लेकिन तब तक मृणाल के इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका था। प्रशंसकों ने मृणाल के इस बेबाक अंदाज की काफी सराहना की है।



पुरी जगन्नाथ के निर्देशन में बन रही पैन इंडिया फिल्म 'स्लम डॉग: 33 टेंपल रोड' में अभिनेत्री तब्बू भी अहम किरदार में नजर आएंगी। फिल्म से तब्बू का लुक सामने आया है जिसे एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। इस एक पोस्टर के जरिए अभिनेत्री ने फैंस को अपने किरदार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिल्म में उनके किरदार का नाम क्या होगा ? और वह कैसा होगा ? 'स्लम डॉग' में तब्बू एक अहम भूमिका निभाने वाली हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर के जरिए अपने फैंस के साथ कुछ खास जानकारीयां साझा कीं। फिल्म में तब्बू एक सख्त

ऑस्कर विजेता अभिनेता, निर्देशक रसेल क्रो के साथ नजर आएंगी प्रियंका

प्रियंका चोपड़ा जोनस और ऑस्कर विजेता अभिनेता, निर्देशक रसेल क्रो एक साथ फिल्म 'ब्लूप्लाई' में नजर आएंगे। यह एक साईंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। इस फिल्म को हॉलीवुड की चर्चित फिल्म 'प्रिडेटर्स' डायरेक्टर निर्मोद पटेल निर्देशित करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 'ब्लूप्लाई' इस फिल्म की शूटिंग इस साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के गॉल्ड कोस्ट में की जाएगी। 'डेडलाइन' के मुताबिक इस फिल्म से लिखा बुमन, गाड डेविस, रुथवन फ्रिगेरियो, ब्रायन कवानाघ जोस, जेसन क्रिगस्टीन, केटी तीरी, स्कॉट लेवेंसन और जेम्स नॉरबरी एग्जीक्यूटिव

प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हैं। फिल्म की कहानी कागों में रहने वाली एक यूएन ट्रांसलेटर की है। वह एक क्रीश प्लेन को खोजने के सीक्रेट मिशन पर है। इस मिशन में उसे कई मुश्किलों का सामना करना

इन फिल्मों में नजर आएंगी

प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड के अलावा भारतीय फिल्मों भी कर रही हैं। वह आठ साल बाद एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी। इस फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आएंगे। फिल्म में पौराणिक कहानियों और साईंस फिक्शन का मिश्रण देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रियंका का नाम बॉन्ड गर्ल के तौर पर चुने जाने के लिए भी सामने आ रहा है।

पड़ता है। आखिर में जब फिल्म की लीड कैरेक्टर विमान के करीब पहुंचती है तो उसे अहसास होता है कि इस प्लेन को कभी वापस नहीं लाना चाहिए था।

